दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता
भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार
27
मार्च-2026

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्षः 09 | अंक : 340 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रूपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह ही बनो... खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा।

राज्य सरकार सच्चा वादा और पक्का काम के ध्येय को साकार करते हुए बढ़ रही है संकल्प से सिद्धि की ओर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण किया

श्री हनुमान लोक का लोकार्पण प्रदेश में रामराज्य की स्थापना के प्रति राज्य सरकार की आस्था का प्रकटीकरण

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सच्चा वादा और पक्का काम के ध्येय को साकार करते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रही है। उज्जैन में 3 साल पहले बाबा महाकाल का महालोक बना। उसके बाद प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थलों को धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आज चैत्र नवरात्रि में पांढुर्णा के जामसांवली मंदिर में श्री हनुमान लोक सहित 362 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन अद्भुत अवसर है। उन्होंने जामसांवली श्री हनुमान लोक के दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए घोषणा की तथा बताया कि यहां श्रद्धालुओं के लिए 10 बिस्तर का छोटा अस्पताल भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीराम नवमी के अवसर पर शुक्रवार को भोपाल से राजा रामचंद्र धाम ओरछा के लिए पीएमश्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ होगा। श्री हनुमान लोक का लोकार्पण प्रदेश में राम राज्य की स्थापना के प्रति सरकार की आस्था को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पांढुर्णा में स्थित जामसांवली मंदिर में श्री हनुमान लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पांढुर्णा को विकास कार्यों की सौगात दी

■ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 111 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और 251 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत के 33 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व-सहायता समूह की बहनों को ऋण स्वीकृति पत्र और किसानों को पट्टों का वितरण किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पांढुर्णा जिले की पहचान संतरे की डलिया भेंट की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश केसाथ मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। खाड़ी में युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री भारत के स्वाभिमान के साथ विदेश नीति पर निर्णय ले रहे हैं। भारत सरकार के संकल्प से ही संकट के समय विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की स्वदेश वापसी संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्री हनुमान ने जीवन में बड़ी चुनौतियों का अडिग रहते हुए सामना किया। प्रभु श्रीराम ने संकट के समय जब भी हनुमान जी को याद किया, उन्होंने पल भर में समस्या का समाधान कर दिया। जय बजरंगबली से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही मन-बुद्धि के साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नव गठित पांढुर्णा जिले में लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति करते हुए अब पांढुर्णा को जिला पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय के भवन की सौगात भी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पांढुर्णा जिले के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

■ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जामसांवली श्री हनुमान लोक के दूसरे चरण के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। पांढुर्णा में 10 एकड़ भूमि पर इंडोर और आउट डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जिले में नगरपालिकाओं के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। पांढुर्णा जिले में महिला पुलिस थाना बनाया जाएगा। सौंसर में कृषि विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्हान नदी पर 30 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से बने पुल, मोहगांव से नांदनवाडी तक 22 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से बनी 24 कि.मी. लंबी सड़क, विभिन्न ग्रामों की नल-जल योजनाओं, नगर पालिका परिषद सौंसर के विभिन्न कार्यों, शासकीय महाविद्यालय पांढुर्णा में अतिरिक्त कक्ष और 4 ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केन्द्रों का लोकार्पण किया।

जिला पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय भवन की सौगात

■ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया, उनमें 69 करोड़ 49 लाख रूपए की लागत से बनने वाला संयुक्त जिला कार्यालय भवन सहित जिला चिकित्सालय और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के विभिन्न विकास कार्य, 21 करोड़ 48 लाख रूपए की लागत से बनने वाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्य, 61 करोड़ 38 लाख रूपए की लागत से पांढुर्णा में बनने वाला रेलवे ओवर ब्रिज प्रमुख हैं। इसके साथ ही सौंसर में अमृत 2.0, राजस्व विभाग के अंतर्गत विभिन्न आवासों, शासकीय उच्चतर विद्यालयों में बनने वाली प्रयोगशालाओं का भी भूमि-पूजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में किसानों को दिन में भी बिजली प्रदाय की जाएगी। किसान फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, दूध उत्पादन और मत्स्य पालन से भी अपनी आय बढ़ाएं। देश के किसान प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी सत्र से शासकीय स्कूलों के बच्चों को माता यशोदा योजना में दूध के निशुल्क टेट्रा पैकेट वितरित किये जाएंगे।

नियमों के बाद दहेज के मामलों में मौत समाज पर गहरा धब्बा, आरोपी की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़ी एक मौत के मामले में एक व्यक्ति की जमानत रद्द करते हुए पटना हाई कोर्ट को कहा कि आरोपी को जमानत देते समय उसको सावधानी बरतनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के मामले में महिला की मौत के मामले में आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया। आरोपी की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के मामलों में महिलाओं की मौत की घटनाओं को समाज पर गहरा धब्बा करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी रोक के बावजूद, इस प्रथा के कारण हजारों महिलाएं

बेमौत मारी जाती हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट का आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। पीठ ने कहा कि दहेज से जुड़ी मौत जैसे बेहद गंभीर अपराध में, हाई कोर्ट को अपने विवेक का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। पीठ ने आगे कहा कि दहेज से जुड़ी मौत के मामले वास्तव में एक गहरी शर्मिंदगी और एक बड़ी सामाजिक बुराई हैं, जो मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन करते हैं। कानूनी रोक के बावजूद, इस प्रथा के कारण हजारों महिलाएं बेमौत मारी जाती है; अक्सर या तो उनकी हत्या कर दी जाती है, या फिर दूल्हे के परिवार की तरफ से पैसे या कीमती चीजों की लालच भरी मांगों के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। दहेज से जुड़ी मौतें समाज पर गहरा धब्बा हैं।

एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी

नई दिल्ली। उड़ान के बीच अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी ने एक इंटरनेशनल सफर को बीच में ही रोक दिया। दरअसल लंदन हीथ्रो जा रहा एयर इंडिया का एयरबस 350 विमान गुरुवार

को बीच सफर से वापस लौट आया। यह फ्लाइट करीब 7 घंटे तक हवा में रहने के बाद तकनीकी खराबी के कारण एहतियातन दिल्ली वापस लौट आई। जानकारी के अनुसार, विमान हीथ्रो एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या सामने आने पर पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वापस लौटने का फैसला किया।

हिंद महासागर में 'खामोश जंग' का शोर, चीन की चालों के बीच भारत ने भी कसी कमर

नई दिल्ली, एजेंसी।

हिंद महासागर में चीन की ग्रे-जोन समुद्री रणनीति के चलते एक खामोश लेकिन अहम रणनीतिक मुकाबला तेज हो गया है, जहां रिसर्च वेसल, समुद्र तल की मैपिंग और पनडुब्बियों की गतिविधियों के जरिए चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में एक ऐसा रणनीतिक मुकाबला चल रहा है, जहां न तो गोलियां चलती हैं और न ही खुली टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन दांव बेहद बड़ा है। चीन अपनी ग्रे-जोन समुद्री रणनीति के तहत चुपचाप भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। चीन के हथियार हैं- रिसर्च वेसल, समुद्र तल की मैपिंग और सबमरीन मूवमेंट। जानकारों के मुताबिक,

चीन के सर्वे जहाज जैसे डोंग फांग होंग-3 लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इन्हें वैज्ञानिक मिशन बताया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इनसे जुटाया गया डेटा भविष्य में सबमरीन ऑपरेशन और सैन्य रणनीति के लिए अहम हो सकता है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पनडुब्बियों की मौजूदगी भी बढ़ाई है। साथ ही कई चीनी जहाज संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते समय अपने ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, ग्वादर, हंबनटोटा और कोलंबो जैसे बंदरगाहों में निवेश कर चीन ने एक तरह का रणनीतिक नेटवर्क भी तैयार किया है।

ओडिशा : विधायकों-मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी पर मचा बवाल सरकार ने तीन गुना सैलरी बढ़ाने वाला बिल लिया वापस

भुवनेश्वर, एजेंसी।

ओडिशा में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में तीन गुना बढ़ोतरी वाले विवादित विधेयकों को सरकार ने वापस ले लिया है। यह फैसला भारी विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद लिया गया। इन विधेयकों से मुख्यमंत्री और विधायकों का वेतन काफी बढ़ने वाला था। ओडिशा में विधायकों और मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर उठे भारी विवाद के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा सचिवालय ने उन सभी संशोधन विधेयकों को वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिनमें वेतन और भत्तों में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। इस फैसले को जनता और विपक्ष के दबाव के बाद उठाया गया कदम माना जा रहा है। विधानसभा सचिव सत्यब्रत राउत ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने इन विवादित विधेयकों को वापस लेने की मंशा जताई है।

1 लाख से बढ़कर 3.45 लाख तक पहुंचने का था अनुमान

क्यों हुआ इतना विरोध और क्या उठे सवाल?

■ इस फैसले के बाद राज्य में व्यापक विरोध शुरू हो गया था। आम जनता से लेकर विभिन्न संगठनों तक ने सवाल उठाए कि क्या इतनी बड़ी वेतन बढ़ोतरी जरूरी थी। लोगों ने इसके समय और जरूरत पर भी सवाल खड़े किए। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन गया।

क्या था वेतन बढ़ोतरी का पूरा मामला?

■ इन विधेयकों के तहत मुख्यमंत्री का वेतन बढ़कर करीब 3.74 लाख रुपये प्रति माह होने वाला था। वहीं विधायकों का वेतन लगभग 1 लाख रुपये से बढ़कर करीब 3.45 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान था। इस बड़े इजाफे के कारण ओडिशा के विधायक देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले नेताओं में शामिल हो सकते थे।

महाराष्ट्र में एक और वीडियो पर बवाल मंत्री जिरवाल के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नरहरि जिरवाल एक कथित आपत्तिजनक वीडियो के चलते विवादों में घिरे हैं। कांग्रेस ने इसे सूबे की राजनीति का नैतिक पतन करार दिया है। विपक्षी पार्टी ने मंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। वहीं, इस मामले में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से ही जारी खींचतान के बाद अब एक कथित वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल इस वीडियो की वजह से चौतरफा घिर गए हैं।

विपक्ष ने क्या कहा?

विपक्ष ने अब इसी वीडियो को आधार बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की गौरवशाली राजनीति के नैतिक पतन का प्रमाण है। जनता के टैक्स के पैसे पर पलने वाले और जिम्मेदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के अनैतिक व्यवहार में शामिल होंगे, तो समाज में क्या संदेश जाएगा?